शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई–पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 48 अंक–18 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 1–8 मई 2023 मूल्य पांच रूपए

दस वर्ष बाद मिली ऐतिहासिक जीत

नेतृत्व की स्थापना की ओर है यह पहला कदम

- 34 में से 24 वार्डों में मिली सफलता
- नीतियों और परिस्थितियों का प्रतिफल है यह जीत
- नादौन और ऊना के उपचुनाव में क्यों मिली है हार

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला के चुनावों में कांग्रेस ने 34 में से 24 सीटें जीतकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। क्योंकि आज तक किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली हैं। इसलिये यह जीत विश्लेषकों के लिये एक रोचक विषय बन गया है। कांग्रेस नेता इसे सरकार की नीतियों का समर्थन करार दे रहा हैं। विपक्ष इसे सत्ता के दुरुपयोग का परिणाम बता रहा है। विपक्ष ने चुनाव के दौरान भी सरकार पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाये हैं। यह अलग बात है कि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया है। लेकिन विश्लेषण के नजरिए से इन आरोपों को हल्के से भी नहीं लिया जा सकता। क्योंकि कुछ मामले शायद अदालत तक भी ले जाये जा रहे हैं। इन चुनावों का विश्लेषण अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों के परिपेक्ष में भी आवश्यक हो जाता है।

नगर निगम शिमला का यह चुनाव एक वर्ष की देरी से हुआ है। इस देरी के कारण यह संयोग घटा कि जो चुनाव सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों में होता था वह सरकार बनने के पांच माह के भीतर ही हो गया। पांच माह का कार्यकाल आम आदमी की नजर में किसी भी सरकार के आकलन के लिये पर्याप्त नहीं होता है। इसलिये स्वभाविक रूप से आम आदमी सरकार के साथ ही जाने का फैसला लेता है। फिर कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में जो गारंटीयां दी हैं उनकी व्यवहारिकता को परखने का भी अभी उचित समय नहीं आया है। इसलिये इन गारटिंयों के फलीभूत होने की उम्मीद भी कांग्रेस के पक्ष में गयी है। फिर इन चुनावों के दौरान शिमला के भवन मालिकों को जो एटीक को रिहाईश योग्य बनाने और बेसमैन्ट को खोलकर उसे गैराज बनाने की सुविधा देने की घोषणा की गयी उनका भी लाभ इन्हीं चुनावों में मिलना स्वभाविक था। क्योंकि एनजीटी के 2016 के फैसले के बाद शिमला में भवन निर्माण एक जटिल समस्या बन गया है। पहले भी भवन निर्माण के लिये यह शहर नौ बार रिटैन्शन पॉलिसियों का लाभ ले चुका है। सरकार की प्लान पर सुप्रीम कोर्ट यह शर्त लगा चुका है की इस संद्धर्भ में आये एतराजों का उचित निपटारा करके इस प्लान को अधिसूचित करें। इस अधिसूचना के बाद भी ऐतराज कर्ताओं को उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देते हुये यह निर्देश दे रखे हैं कि जब तक यह सब फाइनल नहीं हो जाता है तब तक एनजीटी के फैसले की अवहेलना न की जाये। लेकिन आम आदमी को इस सब की जानकारी न होने के कारण सरकार की घोषणा पर विश्वास करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। इसलिये इसका भी चुनावी लाभ मिलना स्वभाविक था।

इसी के साथ राजनीतिक दृष्टि से भी जो राजनीतिक ताजपोशीयां शिमला जिला को अब तक मिल चुकी हैं वह प्रदेश के किसी अन्य जिले को नहीं मिली है। तीन विधानसभा क्षेत्रों में फैली नगर निगम में दो क्षेत्रों में मंत्री होना भी इन चुनावों के लिये लाभदायक रहा है। इसलिये इन चुनावों में मिली इस सफलता को सरकार के पांच माह के फैसलों को जनसमर्थन करार देना थोड़ी जल्दबाजी होगी। बल्कि यह मंथन करना होगा की कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के पाचं वार्डों में हार क्यों मिली। यहां मंथन मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी के बाद की कुछ वार्डों में हार भाजपा के साथ दोस्ती के कारण हुई है अति आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि नगर निगम के चुनावों के साथ ही नादौन बी.डी.सी. और ऊना जिला परिषद के लिये उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। यह हार शिमला की जीत से कुछ अर्थों में ज्यादा बड़ी हो जाती है। क्योंकि शिमला की जीत के बाद यहां की परफारमैन्स लोकसभा चुनाव के लिये एक बड़ा आधार बनेगी यह तय है।

सरकार गिरने के दावे करने वाली भाजपा की हार क्यों हुई

शिमला/शैल। नगर निगम चुनावों में भाजपा को नौ सीटों पर जीत हासिल हुई है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद यह निगम चुनाव भाजपा के लिये पहला चुनावी अवसर था जहां वह अपनी हार को जीत में बदलकर अपनी गुटबाजी पर उठते सवालों को विराम दे सकती थी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका और इस हार ने भाजपा नेतृत्व पर कुछ नये सवाल अवश्य उठा उछाल दिये है। यह सवाल मुख्यमंत्री की भाजपा के साथ दोस्ती की टिप्पणी के बाद और भी गंभीर हो जाते हैं। वैसे तो किसी भी विपक्ष के लिये पांच माह पहले बनी सरकार के खिलाफ मुद्दे तलाशना और उस पर जनता को आकर्षित कर पाना कठिन होता है। लेकिन संयोगवश सुक्खू सरकार के गठन के दूसरे दिन बाद ही जयराम सरकार के अंतिम छः माह के फैसले बदलने से विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा

क्या कहीं मित्रता आड़े आ रही थी

मिल गया जिसे भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार तक न केवल हर चुनाव क्षेत्र तक पहुंचा दिया बल्कि उच्च न्यायालय में भी पहुंचा दिया। पूरे बजट सत्र में इस मुद्दे पर सरकार को घेर रखा। सदन में जब तक सरकार ने यह नहीं कह दिया कि जहां आवश्यक होगा वहां संस्थान खोल दिये जायेंगे तब तक मुद्दे को नहीं छोड़ा।

बजट सत्र तक जो आक्रमकता भाजपा ने सुक्खू सरकार के खिलाफ अपना रखी थी वह निगम चुनाव में उस अनुपात में गायब थी। सरकार पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों को भी चुनाव आयोग तक पूरी गंभीरता से नहीं पहुंचा पायी। भाजपा हाईकमान ने इन चुनावों के लिये प्रभारी भी उत्तर प्रदेश से लगाया। चुनाव के दौरान ही प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री को बदला। लेकिन इसी बीच जब पहले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार और फिर नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार गिरने की भविष्यवाणियां कर डाली तो एकदम स्थितियां बदल गयी। क्योंकि निगम चुनावों के बाद ऐसा क्या घटेगा जिसके परिणाम स्वरूप सरकार गिर जायेगी। इसका कोई खुलासा नहीं किया गया। इससे अनचाहे ही यह आशंका उभर गयी की भाजपा प्रदेश में ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रही है। ऐसे में पांच माह पहले बनी सरकार को गिराने का ताना–बाना बुनने वाले किसी भी विपक्ष को जनता अपना समर्थन क्यों देगी।

सरकार के जिन फैसलों पर बजट सत्र और उससे पहले भाजपा आक्रामक थी उन मुद्दों पर निगम चुनाव में एकदम चुप्पी साधना कहीं न कहीं भाजपा के रणनीतिकारों की मंशा पर सवाल खड़े करता है। जबकि संस्थान बंद करने की चपेट में तो नगर निगम में पडने वाले तीनों विधानसभा क्षेत्र भी आते हैं। यही नहीं निगम में हुई वार्ड बन्दी के खिलाफ मामला उच्च न्यायालय में जा पहुंचा था। वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता सतपाल जैन ने इस मामले की पैरवी की थी। इसमें फैसला भी रिजर्व हो गया था। लेकिन जिस कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की पीठ में या मामला था और रिजर्व कर दिया गया था उसे उनकी सेवानिवृत्ति तक ओपन करवाने का प्रयास तक नहीं किया गया। अब इस मामले की कोई प्रसंगिकता ही नहीं रह गयी है। क्योंकि चुनाव होकर उसके परिणाम भी सामने आ चुके हैं ऐसे में और भी कई प्रकरण हैं जो भाजपा नेतृत्व की मंशा पर ही सवाल खड़े करते हैं।

राज्यपाल ने माता श्री रेणुका जी मंदिर में की पूजा अर्चना

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल तथा लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल दो दिवसीय दौरे के दौरान सिरमौर जिला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री रेणुका जी पहुंचीं। बिरला हेलीपैड, चौरी की धार पहुंचने पर सिरमौर के उपायुक्त सुमित खिमटा ने उनका स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनने के बाद सिरमौर जिला का यह उनका पहला दौरा है।

राज्यपाल ने प्रसिद्ध माता रेणुका जी मंदिर में शीश नवाया और श्री रेणुका झील की परिक्रमा की। उन्होंने भगवान परशुराम मंदिर में पूजा-अर्चना भी की। उन्होंने कहा कि यह स्थान न केवल हिमाचल के लोगों के लिए बल्कि पूरे देशवासियों की आस्था का केंद्र है। राज्यपाल ने कहा कि यह हमारी समृद्ध संस्कृति और उच्च परम्परा को भी दर्शाता है तथा प्रदेश के लोगों की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखने में अहम भूमिका है।

इसके उपरांत राज्यपाल ने श्री रेणुका बांध स्थल का भी दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों से परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी ली और इसकी प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना कार्य को निर्धारित समय में पूरा किया जाए ताकि प्रदेश के साथ अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिल सके।

इस अवसर पर रेणुका के विधायक विनय कुमार, निदेशक श्री रेणुका बांध परियोजना एस.के. चंद्र, जिला वन अधिकारी वन्य जीव अनीता भारद्वाज, डी.एफ.ओ. रेणुका उर्वशी ठाकुर, और जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

हिम स्पोर्ट्स एण्ड कल्चरल एसोसिएशन ने राज्यपाल से भेंट की

शिमला/शैल। हिम स्पोर्ट्स एण्ड कल्चरल एसोसिएशन, शिमला के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष नरेश चौहान, के नेतृत्व में राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट की। उन्होंने इस वर्ष 10 जून से शिमला में एसोसिएशन द्वारा आयोजित किए जा रहे क्रिकेट

टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया।

राज्यपाल ने टूर्नामेंट के आयोजन के लिए एसोसिएशन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन निश्चित रूप से युवाओं को समाज से जोड़ने और नशे जैसी बुराई के खिलाफ कारगर साबित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता है कि युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित किया जाए और इस तरह के आयोजन इस दिशा में सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में खेलों को बड़े स्तर पर प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

इस अवसर पर नरेश चौहान ने राज्यपाल को अवगत कराया कि हिम स्पोर्ट्स एण्ड कल्चरल एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष क्रिकेट एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य युवाओं की खेलों के प्रति रूचि को बढ़ावा देना और उनकी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक दिशा में लगाना है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे जैसी बुराई से दूर रखने और खेलों के माध्यम से उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।

उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में चार टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें राज्यपाल-11, मुख्यमंत्री-11, मुख्य न्यायाधीश-11 और पत्रकार-11 शामिल हैं। इस अवसर पर संघ के महासचिव हरदयाल भारद्वाज भी उपस्थित थे।

सीए स्टोर से किसानों की आर्थिकी होगी सुदृढ़

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने कृषि अनुकूल जलवायु से नवाजा है जिसके फलस्वरूप फल, फूल, सब्जियां, मशरूम, हाप्स, चाय, औषधीय और सुगंधित पौधों जैसे बागवानी उत्पाद यहां सफलतापूर्वक उगाए जा सकते हैं। देश के गर्म आर्द्र तटीय क्षेत्रों में उगाए जाने वाले फलों को छोड़कर, प्रदेश में सम्भवतया अन्य सभी फल उत्पादित किए जा सकते हैं। इन सबके बीच प्रदेश के प्रगतिशील किसानों द्वारा उत्पादित अन्य गुणवत्ता वाले सेब के लिए हिमाचल दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

प्रदेश सरकार ने राज्य के बागवानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। फल उत्पादकों को प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर अपने उत्पाद को घर के समीप बेचने और उन्हें बिचौलियों के चंगुल से बचाने के लिए बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में मार्केट यार्ड और खरीद केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

राज्य के सेब उत्पादकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार यूनिवर्सल कार्टन को लागू करने के लिए कानूनी अध्ययन भी करवा रही है। राज्य के विभिन्न भागों में नियंत्रित वातावरण (सीए) स्टोर खोलने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बागवानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके।

इसके अलावा, सरकार सक्रिय रूप से एक सेब आधारित डिस्टिलरी स्थापित करने पर विचार कर रही है। यह बागवानों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करेगी और वे छोटे आकार और निम्न गुणवत्ता के सेब वाइनरी उत्पादों के लिए बेच सकते हैं। सरकार ने बैंकों को किसानों-बागवानों के कल्याण के लिए उन्हें कृषि, मत्स्य पालन और बागवानी क्षेत्रों के लिए उदारतापूर्ण ऋण प्रदान करने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने वीर जवानों के बलिदान पर शोक व्यक्त किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में आतंकवादियों के विरुद्ध अभियान के दौरान भारतीय सेना के नायक अरविंद कुमार तथा पैराटूपर प्रमोद नेगी की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। अरविंद कुमार जिला कांगड़ा के मरूं गांव और प्रमोद नेगी जिला सिरमौर के शिलाई के निवासी थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वीर जवानों द्वारा मातृभूमि की रक्षा के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा शोक संतप्त परिवारों की हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति से उभरने के लिए शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

बेमौसमी बारिश के दृष्टिगत राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित

आपदा के समय त्वरित कारवाई करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश में लगातार बारिश के कारण हुए नुकसान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी उपायुक्तों को राहत एवं बचाव कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने तथा बेमौसमी बारिश से फसलों को होने वाले नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए।

जगत सिंह नेगी ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल तथा राज्य आपदा मोचन बल को आपदा के समय त्वरित कारवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बैठक के दौरान सम्बंधित अधिकारियों से राहत व बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने राज्य में प्रत्येक पंचायत व ग्राम स्तर पर 8 से 10 स्वयंसेवकों को आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण देने तथा राहत व बचाव कार्यों के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए ताकि किसी भी आपदा के समय राहत व बचाव कार्य तुरंत शुरू किया जा सके। उन्होंने ज़िलों में स्थित होमगार्ड प्रशिक्षण संस्थानों को आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण के लिए उपयोग करने के निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा ने राजस्व मंत्री को आपदा प्रबन्धन अधिनियम के प्रावधानों तथा राजस्व-आपदा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा भूकम्प-रोधी भवनों के निर्माण के लिए मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अस्पताल, विद्यालयों व अन्य प्रमुख भवनों की रैट्रोफिटिंग भी की जा रही है ताकि भूकम्प के समय सम्भावित नुकसान को कम किया जा सके।

बैठक के दौरान विशेष सचिव राजस्व-आपदा प्रबंधन डी.सी. राणा तथा राजस्व-आपदा प्रबन्धन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

बिन्दल ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया

शिमला/शैल। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष

डॉ राजीव बिन्दल ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनावो का परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आया है। भारतीय जनता पार्टी जनमत का सम्मान करते हुए इसे स्वीकार करती है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जीतोड़ मेहनत की और चुनाव अभियान को चरम सीमा तक पहुंचाया। भाजपा का मानना है कि नई बनी हुई प्रदेश कांग्रेस सरकार का प्रभाव नगर निगम चुनाव परिणामों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

डॉ बिन्दल ने भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि इन चुनावों में कार्यकर्ताओं ने हर प्रकार के दबाव के बावजूद भारी मेहनत से चुनावो में पार्टी का काम किया। उन्होंने मतदाताओं का भी आभार व्यक्त किया जिन्होंने भाजपा प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया।

प्रदेश सरकार की अवैध खनन पर नकेल

शिमला/शैल। रेत, बजरी और पत्थर के अवैध खनन एवं राज्य सरकार को बिना आवश्यक कर भुगतान के कारण न केवल पर्यावरण का क्षरण होता है बल्कि राजस्व का भी भारी नुकसान होता है। ऐसे में प्रदेश में वर्तमान अवैध खनन पर रोक लगाने और विभिन्न स्तरों पर अवैध खनन गतिविधियों की जांच के लिए सदस्य विभागों द्वारा की गई कारवाई की समीक्षा के लिए एक कार्यबल गठित किया है।

राज्य सरकार वैज्ञानिक खनन से राजस्व बढ़ाने का प्रयास कर रही है और अवैध खनन पर रोक लगाने को लेकर पूरी तरह गंभीर है। रॉयल्टी की चोरी रोकने और फॉर्म डब्ल्यू.एक्स के सरलीकरण के लिए इसे एम-परिवहन पोर्टल से जोड़ा जाएगा। लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि संबंधित विभागों को भी इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इससे अवैध खनन पर रोक लगेगी और राजस्व हानि पर अंकुश लग सकेगा।

राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न स्थानों पर 'उड़न दस्ते' तैनात किए हैं। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध खनन की जांच के लिए खनन कर्मचारी ऐसे क्षेत्रों में निरंतर छापेमारी कर रहे हैं। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए खनन विभाग के अधिकारी अंतरराज्यीय सीमाओं पर खनन माफिया द्वारा बनाई गई अवैध सड़कों को बाधित कर इनकी खड्डों तक पहुंच को रोकने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने जिलों में गौण खनिजों के अवैध भंडारण एवं अनाधिकृत डीलरों द्वारा इसकी बिक्री के विरुद्ध भी सख्त कारवाई शुरू की है। ग्राम पंचायतों के प्रधानों को अवैध खनन के दुष्परिणामों और निजी भूमि पर खनन पट्टा देने की प्रक्रिया के बारे में ग्राम सामान्य भूमि (निहत और उपयोग) अधिनियम, 1974 के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है।

विभाग ने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा अवैध खनिजों की निकासी के लिए उपयोग में लायी जा रही निजी भूमि की पहचान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। राजस्व विभाग द्वारा इनका सीमांकन पूर्ण होते ही हिमाचल प्रदेश गौण खनिज नियम- 2015 के अनुसार अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर कारवाई की जाएगी और दोषियों पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के लिए जून माह में शुरू होगी निविदा प्रक्रियाः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग को 10 राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया जून, 2023 में आरम्भ करने के निर्देश दिए हैं ताकि इन स्कूलों का निर्माण कार्य शीघ्र-अतिशीघ्र शुरू किया जा सके। उन्होंने शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जिसमें से नादौन, बड़सर, पालमपुर, जयसिंहपुर, शाहपुर, ज्वाली, जसवां-परागपुर, जुब्बल-कोटखाई, किन्नौर और हरोली विधानसभा क्षेत्रों में इसके लिए भूमि शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित कर दी गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में यह विद्यालय आदर्श स्कूल के रूप में स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन विद्यालय भवनों के लिए स्थल अनुरूप विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहले चरण में नर्सरी-पूर्व से पांचवीं कक्षा तक के लिए ब्लॉक निर्मित किए जाएंगे और यह कार्य 18 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे बच्चों का और बेहतर ढंग से व्यक्तित्व विकास हो सकेगा और उनमें आत्मसम्मान की भावना का संचरण होगा और वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा और सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कार्य कर रही है और राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल इस दिशा में एक सकारात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से यह डे-बोर्डिंग स्कूल स्थापित कर विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक ढांचा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और खेल गतिविधियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन स्कूलों में शिक्षेत्तर गतिविधियों के लिए भी प्रबन्ध किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इन स्कूलों की स्थापना के लिए बजट में समुचित प्रावधान किया गया है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग को इन स्कूलों के लिए एक संकल्पना पत्र (कंसेप्ट पेपर) तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसकी समीक्षा के लिए शीघ्र ही एक अन्य बैठक भी आयोजित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का वायदा किया था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी खोले जाएंगे और उन्होंने शिक्षा विभाग को इसके लिए आवश्यक तैयारियां शुरू करने के लिए कहा।

बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, शिक्षा सचिव डॉ. अभिषेक जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पालमपुर में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरितः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ज़िला कांगड़ा के पालमपुर में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग को भूमि हस्तांतरित कर दी गई है तथा इस सम्बंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र ही तैयार कर दी जाएगी। हेलीपोर्ट के लिए प्रस्तावित 82 कनाल भूमि चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में स्थित है जो पालमपुर शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उन्होंने कहा कि हेलीपोर्ट के निर्माण पर लगभग 9 करोड़ रुपए व्यय किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पालमपुर को सूचना प्रौद्योगिकी हब के रूप में विकसित कर रही है तथा इस हेलीपोर्ट के माध्यम से ज़िला कांगड़ा में पर्यटन गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटकों के लिए यात्रा के समय में कमी करने के उद्देश्य से सभी ज़िला मुख्यालयों के समीप हेलीपोर्ट निर्माण करने के लिए प्रयास कर रही है। सभी ज़िला उपायुक्तों को अपने सम्बंधित क्षेत्रों में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आपातकालीन स्थितियों में भी मदद मिलेगी। इससे मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में मरीजों को एयरलिफ्ट करने में भी मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त इन हेलीपोर्ट को किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान निकासी स्थल के रूप में उपयोग किया जा सकता है और संकट के समय में राहत प्रदान की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधोसंरचना को और सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार का कार्य प्रगति पर है और रनवे की लम्बाई 1372 मीटर से बढ़ाकर 3010 मीटर की जाएगी ताकि यहां पर बड़े विमान भी उतर सकें। उन्होंने कहा कि पर्यटन सुविधाओं के विकास से पर्यटकों का आवागमन बढ़ने और युवाओं के लिए रोज़गार के अधिक अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

कौशल आधारित शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता पर बल:रोहित ठाकुर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा क्षेत्र में आशातीत प्रगति की है तथा वर्तमान प्रदेश सरकार कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली विकसित करने पर बल दे रही है। यह बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पेनसिल्वेनिया ग्लोबल तथा एजुकेशन हब (पेन हब) के प्रतिनिधियों के साथ समझौता ज्ञापन की औपचारिकताओं पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति के तहत कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस दिशा में प्रदेश सरकार ने कॉमनवेल्थ ऑफ पेनसिल्वेनिया (पीएएसएसएचई), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के साथ आशय-पत्र हस्ताक्षरित किया है जिसके तहत पेन हब के माध्यम से शैक्षणिक सहभागिता की पहल की गयी है। इस समझौते में उच्च शैक्षणिक संस्थानों के मध्य रणनीतिक सहभागिता तथा परस्पर संपर्क व समय-समय पर ज्ञान आदान-प्रदान कार्यक्रम की मेजबानी पर बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से रोजगारमूलक सहयोगात्मक शोध एवं पाठ्यक्रम कार्यक्रम के साथ-साथ विद्यार्थी आदान-प्रदान कार्यक्रम तथा शिक्षाविदों और प्रशासकों के लिए व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त होगी।

रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार पेन हब के सहयोग से विद्यार्थियों में विविधता, अंतर-सांस्कृतिक जागरूकता तथा आपसी समन्वय में सुधार लाएगी। इससे प्रदेश के विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में संबंध सुदृढ़ होंगे जिससे विविध शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा और हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों को यूएसए में अध्ययन के अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात में कॉमनवेल्थ ऑफ पेनसिल्वेनिया की विशेष दूत कनिका चौधरी ने समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों तथा संभावनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पेन हब समझौता ज्ञापन के सफल कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान करेगा।

बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला के कुलपति प्रो. एस.पी. बंसल ने भी अपने विचार तथा सुझाव साझा किए।

इस अवसर पर निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा, डीन योजना तथा शिक्षक मामले प्रो. अरविंदर कुमार भट्ट तथा प्रो. डॉ.शशिकांत शर्मा भी उपस्थित थे।

हाइड्रोजन के उपयोग से हासिल होगा हरित ऊर्जा राज्य का लक्ष्य

शिमला/शैल। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाईड्रोजन, ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने के लिए एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत होने के अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा का वाहक भी है। हाईड्रोजन, ईंजन वाले वाहन में उपयोग करने पर यह ईंधन केवल बिजली, गर्मी और पानी का उत्सर्जन करता है। वर्तमान में विश्व के अनेक देश जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में हाईड्रोजन का ईंधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं।

प्रदेश में भी हरित ऊर्जा की प्रचुरता है और हाईड्रोजन का उत्पादन कर राज्य सरकार ने इस हरित ऊर्जा के दोहन की पहल की है। इस दिशा में हाल ही में राज्य सरकार ने नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन और विकास में सहयोग के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को भारत का प्रथम हरित ऊर्जा राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ऑयल इंडिया लिमिटेड ने प्रदेश में स्थलीय परियोजनाओं की स्थापना के अतिरिक्त जलाशयों में तैरने वाले सौर संयंत्रों की स्थापना की सम्भावनाओं को तलाशने का निर्णय लिया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड कम्पनी पायलट आधार पर हरित हाईड्रोजन और हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए भी संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए स्थलों का निरीक्षण करने के लिए शीघ्र ही विशेषज्ञों का एक दल भी हिमाचल भेजेगी।

प्रदेश सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड के मध्य यह सहयोग सौर ऊर्जा, हरित हाईड्रोजन, संपीड़ित बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा सहित विभिन्न नई और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से सम्बंधित प्रौद्योगिकी के विकास पर केन्द्रित होगा। यह साझेदारी राज्य में नई ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में सहायक होगी और इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यह क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में भी सहायक सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने एचपी शिवा परियोजना की प्रचार सामग्री का अनावरण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश

उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी, सिंचाई एवं मूल्यवर्धन (एचपी शिवा) परियोजना, 2023-28 की प्रचार सामग्री का अनावरण किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपी शिवा परियोजना के तहत प्रदेश के सात जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर तथा ऊना के 28 विकास खंडों में 162 सिंचाई योजनाओं के माध्यम से लगभग 6000 हैक्टेयर क्षेत्र को 400 बागवानी क्लस्टरों में विकसित किया जाएगा, जिससे लगभग 15000 किसान-बागवान परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में लगभग 60 लाख फल पौधरोपण करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इस परियोजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, जिससे उनकी आय में आशातीत वृद्धि हो सकेगी।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, निदेशक बागवानी संदीप कदम, परियोजना निदेशक एचपी शिवा देवेन्द्र ठाकुर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

जीएसटी संग्रह में 19 प्रतिशत की वृद्धि

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त यूनुस ने बताया कि विभाग ने अप्रैल, 2023 माह में 593 करोड़ रुपए का संग्रह कर जीएसटी में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि गत वर्ष विभाग ने अप्रैल 2022 में 500 करोड़ रुपए का संग्रह किया था।

उन्होंने बताया कि विभाग रिटर्न की निगरानी, रिटर्न की त्वरित जांच, जीएसटी ऑडिट को समय पर पूरा करने और कर अधिकारियों की क्षमता निर्माण पर बल दे रहा है ताकि सेवाओं में सुधार किया जा सके।

उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 13 लाख ई-वे बिलों के सत्यापन का लक्ष्य रखा है। सड़क चैकिंग के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा 94 हजार ई-वे बिलों का सत्यापन किया गया और उल्लंघन करने वालों से अप्रैल 2023 के महीने में 42 लाख रुपए की वसूली की गई।

उन्होंने बताया कि विभाग फर्जी करदाताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और कई ऐसे पंजीकरणों का पता चला है जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं हैं। इन फर्जी करदाताओं के खिलाफ कड़ी कारवाई की जा रही है। विभाग ने हाल ही में कुछ फर्मों का निरीक्षण किया है जिन पर फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट देने में शामिल होने का संदेह है।

विभाग को आशा है कि व्यापक जीएसटी राजस्व वृद्धि परियोजना को लागू करने के बाद डेटा विश्लेषण क्षमताओं में काफी सुधार होगा।

मौन एक बहुत ही अच्छा भाषण है आप अगर इसको अपनायेगे तो धीरे-धीरे आपको भी सारी दुनिया सुनने लगेगी।

...... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

प्रदेश की आर्थिकी पर संभावित श्वेत पत्र

सुक्खू सरकार ने पदभार संभालते ही प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर अपनी चिन्ता जनता से साझा की थी। जनता के सामने यह आंकड़ा रखा था कि उनकी सरकार को विरासत में 75 हजार करोड़ का कर्ज और 11000 करोड़ की देनदारियों मिली हैं। यह आंकड़ा सामने रखते हुये प्रदेश के हालात श्रीलंका जैसे हो जाने की आशंका भी व्यक्त की थी। यह भी कहा था कि वह वित्तीय स्थिति पर बजट सत्र में श्वेत पत्र लायेंगे। बजट सत्र में तो यह श्वेत पत्र नहीं आ पाया लेकिन अब यह श्वेत पत्र तैयार करने के लिए उप-मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसलिये यह उम्मीद है कि यह श्वेत पत्र अब तो आ ही जायेगा। जब किसी परिवार की वित्तीय स्थिति चिन्ताजनक हो जाती है तो सबसे पहले परिवार का मुखिया अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाने की बात करता है और उसके बाद संसाधन बढ़ाने की ओर कदम उठाता है। परिवार की तर्ज पर ही प्रदेश और देश की आर्थिकी चलती है। जब प्रदेश पर इतने कर्ज भार की बात चर्चा में आयी है तब दो पुर्व मुख्य मंत्रियों शान्ता कुमार और प्रेम कुमार धूमल के ब्यान आये हैं। दोनों ने अपने-अपने समय की स्थितियां स्पष्ट की हैं। कांग्रेस के शासनकाल की स्थिति पर पक्ष रखने के लिये आज वीरभद्र हमारे बीच है नहीं और जयराम ने अपने काल को लेकर कोई बड़ी टिप्पणी की नहीं है। वित्तीय स्थिति को लेकर जितने सवाल राजनीतिक नेतृत्व पर उठते हैं उससे ज्यादा वित्त सचिवों पर उठते हैं। वित्तीय प्रबंधन के लिये प्रदेश में एफआरबीएम विधेयक पारित है और इसके मुताबिक सरकार उसी कार्य के लिये कर्ज ले सकती है जिसके निवेश से प्रदेश की आय बढ़े।

इस परिपेक्ष में प्रदेश की जनता को यह जानने का हक है की इतना बड़ा कर्जदार कैसे खड़ा हो गया है? यह कर्ज लेने की आवश्यकता कब और क्यों पड़ी? यह कर्ज कहां-कहां निवेश हुआ है और उससे कब-कब कितनी आय बढी? इस समय कैग रिपोर्टों के मुताबिक कर्ज का ब्याज चुकाने के लिये भी कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य की समेकित निधि से अधिक खर्च किया जा रहा है जो कि संविधान की अवहेलना है। और कई कई वर्षों तक ऐसा खर्च नियमित नहीं हो पाता है। हर वर्ष की रिपोर्ट में इसका जिक्र रहता है। बजट दस्तावेजों में किसी समय राज्य की आकस्मिक निधि का आंकड़ा दर्ज रहता था जो अब गायब है।

राज्य सरकार हर वर्ष बजट में राजस्व आय का आंकड़ा रखती है। राजस्व आय के साथ इतना बड़ा कर्जदार कैसे खड़ा हो गया आज जब वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार किया ही जा रहा है तो यह पूरी स्पष्टता के साथ की सरकार जनता को राहत देने के नाम पर कर्ज लेकर घी पीने को ही चरितार्थ तो नहीं करती रही है। क्योंकि बेरोजगारी में प्रदेश देश के पहले छः राज्यों में आ चुका है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यह सब तब हो रहा है जब कुछ उद्योगपतियों के सहारे जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। यह सब आंकड़े योजनाओं के अन्त विरोध के परिचायक होते हैं। इनके सहारे कुछ लोगों को कुछ समय के लिये ही बहकाया जा सकता है। लेकिन स्थाई तौर पर नहीं इसलिए श्वेत पत्र के सारे पक्ष सामने आने चाहिये ताकि लोग उस पर विश्वास कर सकें।

निराश्रित बच्चों के सपनों को सुखाश्रय ने लगाए स्वाभिमान के पंख

अभिभावक के रूप में बच्चों का सुनहरी भविष्य बुनेगी सुख की सरकार

शिमला। सुखाश्रय ने निराश्रित बच्चों के सपनों को साकार करने में स्वाभिमान के पंख लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निराश्रितों को चिल्ड्रन आफ स्टेट का दर्जा दिया गया है। अब सरकार अभिभावक के रूप में निराश्रितों की उचित देखभाल सुनिश्चित करेगी। सरकार की इस पहल में निराश्रित बच्चों को अपना भविष्य भी सुनहरा दिखाई दे रहा है। मंडी जिला की बात करें तो विभिन्न बालश्रमों तथा चाइल्ड केयर संस्थानों में जीवन यापन कर रहे 383 निराश्रित बच्चे लाभावित होंगे। सुखाश्रय योजना के आरंभ होने पर निराश्रित बच्चों के चेहरों पर रौनक देखते ही बनती है।

अब हिमाचल में 27 वर्ष तक की आयु के निराश्रित बच्चों की सरकार अभिभावक की भूमिका निभाएगी। अनाथ बच्चे किसी भी तरह की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे वो एमबीबीएस या आईआईटी ही क्यों न हो, इसकी पूरी फीस और हॉस्टल का सारा खर्च सरकार वहन करेगी। इसके अतिरिक्त प्रतिमाह 4000 रुपये पॉकेट मनी अलग से दी जाएगी।

अनाथ बच्चे साल में एक बार हवाई जहाज से शैक्षणिक भ्रमण कर पाएंगे। उनके भारत के किसी भी राज्य में आने जाने और ठहरने का पूरा खर्च भी सरकार उठाएगी। जिस भी प्रदेश में जाएंगे उन्हें तीन स्टार होटल में ठहराया जाएगा। 10 हजार उनको कपड़ों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। स्वरोजगार के लिए भी आर्थिक मदद दी जाएगी इसके अतिरिक्त 27 वर्ष की आयु के उपरान्त घर बनाने के लिए भी जमीन भी सरकार उपलब्ध करवाएगी।

सरकाघाट के भरनाल में दीन बंधु बाल-बालिका आश्रम के दसवीं के छात्र जितेंद्र कुमार तथा नवम कक्षा के छात्र धर्मेंद्र, सातवीं कक्षा के छात्र भूपेंद्र ने सरकार द्वारा सुखाश्रय योजना आरंभ करने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि पहली बार किसी सरकार ने निराश्रित बच्चों को निशुल्क शिक्षा, कोचिंग तथा त्यौहार भत्ता देने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने सभी निराश्रित बच्चों को स्वाभिमान से जीने के लिए पहल की है इस के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु का धन्यवाद करते हैं। दीन बंधु बाल-बालिका आश्रम के संस्थापक प्रेम सिंह का कहना है कि वह पिछले 36 वर्षों से निराश्रित बच्चों के लिए बाल आश्रम का संचालन कर रहे हैं लेकिन पहली मर्तबा किसी सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए सराहनीय कार्य किया है।

बालिका देखभाल संस्थान सुंदरनगर की जाहनवीं, लता, शिल्पा, किरण तथा प्रिया कुमारी ने सुखाश्रय आरंभ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कभी हम सपने में भी यह नहीं सोच सकते थे कि हमें निशुल्क उच्च शिक्षा के साथ साथ हवाई यात्रा के लिए कभी कोई मदद करेगा लेकिन यह सब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने निराश्रित बच्चों के लिए एक अभिभावक की तरह कर दिखाया है।

विशेष योग्यता प्राप्त छात्राओं की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंदरनगर में नवम कक्षा की छात्र सृष्टि चौहान तथा शशि का कहना कि सुखाश्रय निराश्रित बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खु ने निराश्रित बच्चों की पीड़ा को समझा है और सरकार ने प्राथमिकता के तौर पर चिल्ड्रन आफ स्टेट का दर्जा दिया है।

उपायुक्त डा. अरिंदम चौधरी ने कहा कि निराश्रित बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी में इस शिवरात्रि महोत्सव के दौरान भी निराश्रित बच्चों को विशेष तौर पर मंच उपलब्ध करवाया गया है इसी तरह से सरकार की ओर से सुंदरनगर में आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर के लिए भी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं।

राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में आएगी नील क्रांति

शिमला। देश के समुद्री क्षेत्र से लेकर हिमालय से निकली वाली नदियों में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। जैव विविधता के दृष्टिगत मत्स्य क्षेत्र में रोज़गार व स्वरोज़गार की अपार संभावनाएं हैं। यह क्षेत्र लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

हिमाचल प्रदेश को ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियों का आशीर्वाद प्राप्त है। यह नदियां पहाड़ी और अर्ध-मैदानी क्षेत्रों को समृद्ध करती हैं। प्रदेश में बहने वाली बारहमासी नदियों ब्यास, सतलुज और रावी में कई धाराएं और कई सहायक नदियां समाहित होती हैं। यह नदियां शिजोथोरैक्स, गोल्डन महसीर और विदेशी ट्राउट जैसी ठडे पानी की मछलियों की कई प्रजातियों की आश्रय स्थली हैं।

प्रदेश में महत्वाकांक्षी इंडो-नॉरविजियन ट्राउट पालन परियोजना के सफल कार्यान्वयन ने विकसित तकनीकों के उपयोग से प्रदेश के लोगों की जल संसाधनों के उपयोग में रुचि पैदा की है। गोबिंद सागर और पौंग बांध, चमेरा और रणजीत सागर बांध में महत्वपूर्ण मछली प्रजातियां के पालन और उत्पादन से स्थानीय लोगों को अपनी आर्थिकी सुदृढ़ करने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में मछली पालन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत प्रदेश सरकार राज्य में मत्स्य पालन और इससे संबंधित व्यवसायों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और इस दिशा में कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

राज्य सरकार बैकयार्ड फिश फार्मिंग, केज कल्चर, री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और अन्य तकनीक आधारित मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है।

वर्तमान वित्त वर्ष में निजी क्षेत्र में 20 हेक्टेयर नये मत्स्य तालाबों का निर्माण किया जायेगा। मत्स्य पालन के माध्यम से राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य तालाबों के निर्माण पर 80 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है। मत्स्य क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए 120 नई ट्राउट इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।

राज्य में मत्स्य पालन से जुड़े किसानों एवं अन्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण की सुविधा हेतु जिला ऊना के गगरेट में 5 करोड़ रुपये की लागत से कार्प फार्म स्थापित किया जायेगा। इस केंद्र में हर साल 600 मछुआरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले नदी की मछलियों पर आश्रित मछुआरों को 1000 फैंकवा जाल उपदान पर प्रदान किए जाएंगे। राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने 11.26 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस राशि का उपयोग प्रदेश में मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्य में मत्स्य पालन के माध्यम से इससे जुड़े लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं।

प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान देगा 'हिम-क्राफ्ट': मुख्यमंत्री

हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए तैयार होगी विपणन रणनीति

शिमला। हिमाचल प्रदेश अपनी विभिन्न कलाओं तथा अभिभूत कर देने वाले हस्तशिल्प उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों को एक नए ब्रांड के रूप में वैश्विक बाजार में पहचान दिलाने तथा 'हिम-क्राफ्ट' को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विपणन रणनीति विकसित करने पर विचार कर रही है। इससे राज्य तथा यहां के कारीगरों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

वर्तमान प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम, सीमित को एक नई पहचान प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठा रही है जिसके तहत राज्य के हथकरघा तथा हस्तशिल्प उत्पादों को अब 'हिम-क्राफ्ट' के ब्रांड नाम से जाना जाएगा। इस पहल से जहां कारीगरों को उनके हुनर के अनुसार उचित दाम मिलेंगे, वहीं प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को भी संबल मिलेगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आधुनिक बाजार में ब्रांडिंग तथा विपणन बेहद आवश्यक हैं। इसी के दृष्टिगत प्रदेश के कारीगरों तथा बुनकरों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प व हथकरघा उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए 'हिम-क्राफ्ट' ब्रांड सहायक सिद्ध होगा। इन उत्पादों को एक ब्रांड के बतौर सृजित करने से जहां लोगों का इन पर विश्वास और बढ़ेगा, वहीं उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं की मांग भी बढ़ेगी।

यह ब्रांड नाम हथकरघा तथा हस्तशिल्प उत्पादों को एकीकृत रूप से बाजार में प्रस्तुत एवं स्थापित करने में भी मदद करेगा। इसके प्रचार के लिए भी व्यापक रणनीति बनाई गई है और व्यावसायिक कार्ड, लैटरहेड ई-मेल हस्ताक्षर तथा आधिकारिक वेबसाइट सहित सभी आधिकारिक दस्तावेजों में यह ब्रांड प्रदर्शित किया जाएगा।

घरेलू तथा वैश्विक बाजार में प्रदेश के कारीगरों द्वारा तैयार हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों की बहुत मांग है। 'हिम-क्राफ्ट' द्वारा जी-20 सम्मेलन के प्रतिनिधियों को उपहारस्वरूप प्रदान करने के लिए तैयार किए गए उत्पादों की खूब सराहना की गई। हाल ही में जनता के लिए खोले गए मशोबरा स्थित 'प्रेजीडेंट रिट्रीट' में भी प्रदेश के ऐसे उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं।

हस्तशिल्प और हथकरघा हिमाचली संस्कृति का एक अभिन्न अंग हैं और इसमें प्रदेश के समृद्ध इतिहास की झलक दिखाई देती है। राज्य में बुनाई, कढ़ाई, लकड़ी पर नक्काशी, धातु के कार्य, मिट्टी के बर्तन आदि की समृद्ध परंपरा रही है और यह पारंपरिक हस्तशिल्प पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। इनमें आधुनिक तकनीकों और डिजाइनों को शामिल कर हस्तशिल्पों का समय के साथ सतत विकास हुआ है। राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर इनके प्रचार व बाजार सहभागिता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बेहतर विपणन रणनीति और ब्रांड नाम उपयोगी हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार एक विपणन रणनीति विकसित करने की योजना बना रही है। नए ब्रांड नाम की एक वेबसाइट होगी जिसके माध्यम से उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया में उपस्थिति बढ़ाने सहित विज्ञापन अभियान संचालित किए जाएंगे। इन सभी उपायों के माध्यम से राज्य के कारीगरों के जीवनस्तर को उन्नत बनाने में मदद मिलेगी।

हस्तशिल्प से जुड़े कारीगरों सहित समाज के विभिन्न वर्गों ने 'हिम-क्राफ्ट' ब्रांड नाम का स्वागत किया है तथा उम्मीद जताई कि इससे निगम की उत्पादकता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनका मानना है कि हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड की 'हिम-क्राफ्ट' के रूप में पुन: ब्रांडिंग राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने, कारीगरों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में कारगर कदम है।

'पर्यावरण एक अनुकूल जीवन शैली' को अपनाने का संकल्प

शिमला। विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) एक ऐसा अवसर है जो पर्यावरण के लिए जागरूकता और कारवाई के लिए देश भर के लाखों लोगों को एक साथ लाता है। इस वर्ष, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने मिशन एलआईएफ़ई-यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली पर बल देते हुए

विश्व पर्यावरण दिवस 2023 मनाने की

परिकल्पना की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ग्लासगो में वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा (यूएनएफसीसीसी)-2021 के 26 देशों के सम्मेलन-सीओपी 26 में विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में एलआईएफ़ई, यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली की अवधारणा पेश की गई थी, जब उन्होंने स्थायी जीवन शैली और प्रथाओं को अपनाने के लिए एक वैश्विक प्रयास को फिर से शुरू करने का आहवान किया था। समारोह के उपलक्ष्य में एलआईएफ़ई पर देश भर में जन भागीदारी का आयोजन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (एनएमएनएच)

राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (एनएमएनएच) ने राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (एनजेडपी) के सहयोग से स्कूल और पशु चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए ह्रिसाइकिल रैली और एक बातचीत के सत्र का आयोजन किया। विद्यार्थियों ने अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण एक अनुकूल जीवन शैली के आंदोलन को अपनाने का संकल्प

लिया। अभियान के दूसरे दिन की शुरुआत कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, अशोक प्लेस, बंगला साहिब मार्ग, नई दिल्ली के 155 स्कूली विद्यार्थियों और उत्तर प्रदेश के पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा के 55 विद्यार्थियों के चिड़ियाघर भ्रमण के साथ हुई। दौरे के बाद, प्रतिभागियों को मिशन लाइफ़ यानी पर्यावरण एक अनुकूल जीवन शैली के उद्देश्यों से परिचित कराया गया और मिशन-लाइफ़ पर एक प्रतिज्ञा भी हुई, जिसके बाद प्रतिभागियों ने मिशन लाइफ़ को बढ़ावा देने के लिए कारवाई का पालन करने की व्यक्तिगत प्रतिज्ञा की। इन गतिविधियों के अलावा, प्रतिभागियों को मिशन लाइफ पर एक फिल्म भी दिखाई गई।

दिन की समाप्ति एक साइकिल रैली के साथ हुई जिसका उद्देश्य मिशन लाइफ यानी पर्यावरण एक अनुकूल जीवन शैली के अंतर्गत ऊर्जा बचाओ विषय को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रीय प्राणि उद्यान में इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य प्रकृति से जुड़े रहकर सतत जीवन शैली की धारणा को प्रोत्साहन देने के लिए जागरूकता पैदा करना और लोगों को जोड़ना था। वोट फॉर लाइफ के नारों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

प्राकृतिक इतिहास के क्षेत्रीय संग्रहालयों द्वारा कार्यक्रम

मैसूर के राष्ट्रीय प्राकृतिक

इतिहास संग्रहालय (आरएमएनएच) ने विद्यार्थियों और आम जनता के लिए मिशन लाइफ (पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली) के हिस्से के रूप में कैंपस में पेड़ों की गिनती की गतिविधि का आयोजन किया और बातचीत/ग्रीन टॉक के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली की आवश्यकता पर बल दिया।

भुवनेश्वर के राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (आरएमएनएच) ने मदर्स पब्लिक स्कूल, भुवनेश्वर के 200 विद्यार्थियों के लिए मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के हिस्से के रूप में पेड़ों की छाल और उनसे जुड़े विभिन्न प्रकार के कीड़ों को जानने और समझने के लिए कैंपस में पेड़ों को गले लगाने की गतिविधि का आयोजन किया गया।

जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया

जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक डॉ. धृति बैनर्जी ने मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली पर जागरूकता फैलाने और जन भागीदारी के लिए पश्चिम बंगाल के बर्दवान विश्वविद्यालय के लगभग 120 विद्यार्थियों को ''सतत पर्यावरण के लिए पशु विविधता की भूमिका'' विषय पर संबोधित किया।

01 अप्रैल, 2024 से स्टॉम्प पेपर पूर्ण रूप से बंद

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि 18 वर्ष तथा इससे अधिक आयु की स्पीति घाटी की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में प्रतिमाह 1500 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसमें छोमो या नन भी शामिल हैं।

बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत-पत्र तैयार करने के लिए उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमण्डलीय उप-समिति गठित की जाएगी, जिसमें कृषि मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

मंत्रिमण्डल ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टॉम्प ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में ई-स्टॉम्पिंग आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि स्टॉम्प पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए तथा स्टॉम्प विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए। मंत्रिमण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि एक अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक स्टॉम्प पेपर तथा ई-स्टॉम्प पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा तथा 01 अप्रैल, 2024 से भौतिक रूप से स्टॉम्प पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे।

बैठक के दौरान सभी पात्र विद्यार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण के माध्यम से स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपए प्रदान किए जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने बजट घोषणा के अनुसार राजस्व विभाग के नम्बरदारों के मानदेय को 3200 रुपए से बढ़ाकर 3700 रुपए प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से प्रदेश के 3177 नम्बरदार लाभान्वित होंगे।

बैठक के दौरान राजस्व चौकीदार तथा अंशकालिक कार्यकर्ता के मानदेय को 5 हजार रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश के लगभग 1950 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।

मंत्रिमण्डल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया जिसके तहत सौर ऊर्जा तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पट्टे पर, खरीद, अधिग्रहण आधार पर स्थापित करने के लिए भूमि हस्तांतरण किया जा सकता है। यह निर्णय इस सम्बंध में विभिन्न अधिनियमों के लागू प्रावधानों के तहत कार्यान्वित होगा।

बैठक के दौरान राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने, उच्च न्यायालय को छोड़कर दीवानी न्यायालयों में शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फीस को 6 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने तथा अटल टनल योजना क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया। अटल टनल योजना क्षेत्र में ज़िला लाहौल-स्पिति के राजस्व गांव भी शामिल हैं।

बैठक के दौरान पान मसाला, पान चटनी तथा तम्बाकू या तम्बाकू पदार्थों वाले सभी तम्बाकू उत्पादों पर सर्टन गुड्स कैरेड वाई रोडज़ (सीजीसीआर) टैक्स को 3 रुपए से बढ़ाकर 4.50 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों तथा जूनियर ड्राफ्टसमेन के 30 पदों को भरने को मंज़ूरी प्रदान की।

बैठक के दौरान जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पदों तथा जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 50 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के 3 रिक्त पदों तथा ज़िला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में लैक्चरर के 4 पदों को भरने को मंज़ूरी प्रदान की।

राज्य के नीति निर्माण और सुशासन में सहायक सिद्ध होगा डाटा पोर्टलः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। सभी सरकारी विभागों का डाटा एकीकृत करने के लिए 'हिम डाटा पोर्टल' प्लेटफार्म के विकास के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में प्रदेश सरकार एवं इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनेस के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

प्रदेश सरकार की ओर से सचिव सूचना प्रौद्योगिकी डॉ.अभिषेक जैन तथा इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनेस की ओर से कार्यकारी निदेशक प्रो. अश्विनी छत्रे ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हिम डाटा पोर्टल' के विकास के लिए इण्डियन स्कूल ऑफ बिजनेस सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ सहयोग करते हुए अनुसंधान और तकनीकी सहायता भागीदार के रूप में कार्य करेगा। यह डाटा पोर्टल उच्च श्रेणी के विश्लेषणात्मक डाटा सैट और आइडेंटिटी-एक्सेस-मैनेजमेंट-कन्ट्रोल्ड डैशबोर्ड और रिपोर्ट इत्यादि के माध्यम से राज्य के नीति निर्माण और सुशासन में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल 'हिम पल्स' के माध्यम से राज्य की लाभ वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करेगा और इससे 'हिम परिवार' की क्षमता में भी वृद्धि होगी और लक्षित जनसंख्या को विभिन्न लाभ प्रदत्त करने के लिए उनकी डिजिटल पहचान को लिंक करने में यह सहायक होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते से राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हिम डाटा पोर्टल विभिन्न विभागों के बहुमूल्य डाटा को विभिन्न डोमेन से एकत्र करेगा और इससे प्रशासन में दक्षता को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से संबंधित एक वैबसाइट भी विकसित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम पल्स एक आधुनिक डेटा विश्लेषण एप्लीकेशन है, जो प्रशासन में विस्तार, अन्तिम व्यक्ति तक पहुंच और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए विकसित की गयी है। उन्होंने कहा कि यह सरकारी कार्यक्रमों और प्रणालियों से आम नागरिकों को वास्तविक समय में डिजिटल डाटा के माध्यम से जोड़ने में सहायक होगा और इससे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हाई रेज्योल्यूशन सामाजिक एवं आर्थिक प्रोफाइल और सैटेलाइट इमेज़ के संयोजन का लाभ भी मिल सकेगा।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक इन्द्र दत्त लखनपाल तथा नीरज नैयर, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मुकेश रेपसवाल, इण्डियन ऑफ स्कूल बिजनेस की आरुषि जैन और अपूर्वा भी उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री ने लाहौल-स्पिति ज़िला के लिए चार बचाव वाहनों को हरी झंडी दिखाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ज़िला लाहौल-स्पिति के लिए बचाव कार्यों, कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा शरद ऋतु में बर्फबारी तथा अन्य आपदाओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया के लिए चार फोर्स गुरखा वाहनों को हरी झंडी दिखाई। आई.सी.आई.सी.आई. फाऊंडेशन द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत यह वाहन प्रदान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वाहन शून्य से लेकर माइनस 30 डिग्री तापमान वाले क्षेत्रों में प्रभावी सिद्ध होंगे। इन वाहनों की इंजन क्षमता तथा ग्राउंड क्लीयरेंस बेहतर है, जो लाहौल-स्पिति की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि ज़िला में बादल फटने तथा हिमस्खलन जैसी घटनाएं आम हैं। ऐसे में आम जनता की कठिनाईयों को कम करने एवं राहत व बचाव कार्यों में इन वाहनों से मदद मिलेगी। यह वाहन बचाव दल तथा अन्य उपकरणों के तीव्र आवागमन में सहायक सिद्ध होंगे, जिससे बहुमूल्य जानें बचाई जा सकेंगी।

लाहौल-स्पिति ज़िला के लिए यह वाहन प्रदान करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए विधायक रवि ठाकुर ने कहा कि यह कदम प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के लोगों के प्रति मुख्यमंत्री की संवेदनाओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के हाल ही में स्पिति घाटी के प्रवास के दौरान यह मुद्दा उठाया गया था और सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर लोगों की इस मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि स्पीति घाटी की जनता मुख्यमंत्री की इस उदारता के लिए आभारी है।

मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ का नया झंडा, लोगो और वर्दी लोकार्पित की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल (एच.पी. एसडीआरएफ) का नया झंडा, निशान (लोगो) तथा वर्दी लोकार्पित की और 10 वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एक पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल एक आपदा-सम्भावित क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश एसडीआरएफ का नया झंडा, लोगो, वर्दी और वाहन राज्य आपदा मोचन बल की निष्ठा और समर्पण के साथ प्रदेश के लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज का यह लॉन्च राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं में वृद्धि की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में इस बल ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बहुमूल्य जीवन और संपत्ति को बचाने में कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपदाओं के दौरान विभिन्न बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि नए लॉन्च किए गए संसाधन एचपी एसडीआरएफ को प्रदेश के लोगों की और प्रभावी ढंग से सेवा करने में सक्षम बनाएंगे।

पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने इस अवसर पर कहा कि एसडीआरएफ की स्थापना हाल ही में हुई है और पिछले कुछ महीनों में इस बल ने प्रदेश के नागरिकों की कुशलता से सेवा की है। इस बल की तीन कम्पनियां शिमला, मंडी और कांगड़ा में स्थित हैं, जिनमें वर्तमान में 183 कर्मचारी कार्यरत हैं।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक रवि ठाकुर, आई.डी. लखनपाल और सुरेश कुमार, एडीजीपी कानून व्यवस्था अभिषेक त्रिवेदी और एसडीआरएफ की प्रमुख और पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

दस साल बाद शिमला नगर निगम में कांग्रेस की जीत

शिमला/शैल। कांग्रेस ने 10 साल बाद शिमला नगर निगम चुनावों में 34 सीटों में से 24 सीटों पर जीत हासिल कर नगर निगम पर कब्जा कर लिया है। जबकि भाजपा ने नौ और सीपीआईएम ने एक सीट पर जीत हासिल की है। चुनावी नतीजों पर नजर डाले तो दस सीटों पर हार-जीत का अन्तर 100 से भी कम का रहा है। जिसमें भाजपा ने दो सीटें वार्ड नंबर-2 में 27 वोटों के अन्तर और वार्ड नंबर-13में 23 वोटों के अंतर से जीती है जबकि वार्ड नंबर 33 से कांग्रेस का उम्मीदवार सबसे कम 8 वोटो के अंतर से जीत हासिल कर पाया है। भाजपा ने जिन 9 सीटों में जीत हासिल की है उनमें से भी दो तीन को छोड़कर बाकी सभी में जीत का अंतर ज्यादा नही रहा है।

वार्ड नं. 1 भराड़ी में कुल 1612 मतों में से

1. जितेन्द्र चौधरी को 604
2. **मीना चौहान को 986 विजयी भाजपा**
3. शाम लाल को 11
4. नोटा को 11 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 2 रूलदूभटटा में कुल 2166 मतों में से

1. **सरोज ठाकुर को 1082 विजयी भाजपा**
2. सत्या वर्मा को 1055
3. अतुला सूद को 16
4. नोटा को 13 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 3. कैथू में कुल 1703 मतों में से

1. **कान्ता सुयाल को 1021 विजयी कांग्रेस**
2. कमलजीत को 659
3. नोटा को 23 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नं. 4 अनाडेल में कुल 1856 मतों में से

1. सपना कश्यप को 837
2. **उर्मिला कश्यप को 1002 विजयी कांग्रेस**
3. नोटा को 17 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 5 समरहिल में कुल 1810 मतों में से

1. शैली शर्मा को 481
2. जगदीश ठाकुर को 609
3. **वीरेन्द्र ठाकुर को 687 विजयी सीपीआईएम**
4. बाबूराम नाहर को 15
5. नोटा को 18 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 6 टुटू में कुल 1617 मतों में से

1. मीनाक्षी गोयल को 508
2. **मोनिका भारद्वाज को 669 विजयी कांग्रेस**
3. दीक्षा ठाकुर को 426
4. नोटा को 14 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 7 मज्याठ में कुल 1099 मतों में से

1. **अनिता शर्मा को 875 विजयी कांग्रेस**
2. निर्मला चौहान को 218
3. नोटा को 6 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 8 बालूगंज में 1378 मतों में से

1. किरण बाबा को 537
2. **दलीप थापा को 816 विजयी कांग्रेस**
3. राम गोपाल को 21
4. नोटा को 04 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नं. 9 कच्चीघाटी में कुल 1619 मतों में से

1. अलका कंवर को 753
2. आम आदमी पार्टी की सरिता सिंह को 27
3. **किरण शर्मा को 825 विजयी कांग्रेस**
4. नोटा को 14 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 10 टूटीकण्डी में कुल 1924 मतों में से

1. रमला बिजलवान को 39
2. **उमा कौशल 1193 विजयी कांग्रेस**
3. रितु गौतम को 672
4. नोटा को 20 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नं. 11 नाभा में कुल 1579 मतों में से

1. **सिमी नंदा को 855 विजयी कांग्रेस**
2. हिमा देवी को 708
3. नोटा को 16 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नं. 12 फागली में कुल 1674 मतों में से

1. **कल्याण चन्द धीमान को 872 विजयी भाजपा**
2. रूप चन्द को 759
3. धीरज को 17
4. नोटा को 26 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नं. 13 कृष्णानगर में कुल 2303 मतों में से

1. **बिट्टू कुमार 865 विजयी भाजपा**
2. अनिता को 16
3. राज पाल को 134
4. अमित 180
5. विप्पन सिंह को 842
6. सोहन लाल को 249
7. नोटा को 17 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नं. 14 रामबाजार में कुल 1763 मतों में से

1. सुनन्दा करोल को 857
2. **सुषमा कुठियाला को 891 विजयी कांग्रेस**
3. नोटा को 15 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 15 लोअर बाजार में कुल 1349 मतों में से

1. भारती सूद को 480
2. मीरा कुकरेजा को 13
3. **उमंग बांगा को 842 विजयी कांग्रेस**
4. नोटा को 14 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नं. 16 जाखू में कुल 1055 मतों में से

1. राजन अग्रवाल को 366
2. **अतुल गौतम को 679 विजयी कांग्रेस**
3. नोटा को 10 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नं. 17 बैनमोर में कुल 1514 मतों में से

1. अनुप वैद को 683
2. **शीनम कटारिया को 799 विजयी कांग्रेस**
3. अपूर्व शर्मा को 16
4. नोटा को 16 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न.18 ईन्जनघर में कुल 1679 मतों में से

1. आरती चौहान को 172
2. सुधीर को 42
3. विकास थापटा को 575
4. **अंकुश वर्मा 881 विजयी कांग्रेस**
5. नोटा को 09 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नं.19 संजौली चौक में कुल 2025 मतों में से

1. सत्या कौन्डल को 905
2. **ममता चन्देल को 1101 विजयी कांग्रेस**
3. नोटा को 19 मत प्राप्त हुए

वार्ड नं. 20. अप्पर ढल्ली में कुल 1384 मतों में से

1. नरेन्द्र चौहान को 654
2. **कमलेश को 724 विजयी भाजपा**
3. नोटा को 6 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 21 लोअर ढल्ली में कुल 1397 मतों में से

1. **विशाखा मोदी को 880 विजयी कांग्रेस**
2. संगीता को 501
3. नोटा को 15 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 22 शांन्ति विहार में 1558 मतों में से

1. **विनीत शर्मा को 1118 विजयी कांग्रेस**
2. देवेन्दर शर्मा को 413
3. हरविंदर सिंह को 18
4. नोटा को 09 मत प्राप्त हुए।

वार्ड नं. 23 भट्टाकुफर में कुल 1066 मतों में से

1. **नरेन्दर ठाकुर को 700 विजयी कांग्रेस**
2. सुशांत चौहान को 358
3. नोटा को 08 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 24 सांगटी में कुल 2207 मतों में से

1. कमल किशोर ठाकुर को 520
2. **कुलदीप ठाकुर को 983 विजयी कांग्रेस**
3. गुरूनाम सिंह को 11
4. सी0पी0आई0एम0 के कपिल देव को 684
5. नोटा को 09 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 25 मल्याणा में 784 मतों में से

1. अम्बिका ठाकुर को 368
2. **शांता वर्मा को 407 विजयी कांग्रेस**
3. आम आदमी पार्टी की विमला देवी को 06
4. नोटा को 03 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 26 पंथाघाटी में 1185 मतों में से

1. कुसुम चौहान को 274
2. नेहा ठाकुर को 239
3. **कुसुम ठाकुर को 645 विजयी भाजपा**
4. आम आदमी पार्टी की तरुणा मिश्रा को 18
5. नोटा को 09 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 27 कसुम्पटी में 1553 मतों में से

1. **रचना शर्मा को 907 विजयी भाजपा**
2. लक्ष्मी चौहान को 628
3. संगीता को 08
4. नोटा को 10 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 28 छोटा शिमला में 2253 मतों में से

1. **सुरेन्द्र चौहान को 1397 विजयी कांग्रेस**
2. संजीव लाल को 11
3. संजीव चौहान (पिंकू) को 840
4. नोटा को 04 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 29 विकासनगर में 2319 मतों में से

1. रमा कुमारी को 524
2. सोनम पंवर को 09
3. **रचना भारद्वाज को 1297 विजयी कांग्रेस**
4. मंजुला चौहान को 481
5. नोटा को 08 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 30 कंगनाधार में 1090 मतों में से

1. रेनू चौहान को 451
2. दिना नाथ शर्मा को 43
3. जीवन कुमार शर्मा को 36
4. **राम रत्न वर्मा को 549 विजयी कांग्रेस**
5. नोटा को 11 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 31 पटयोग में 1460 मतों में से

1. **आशा शर्मा को 690 विजयी भाजपा**
2. हरीश कुमार को 128
3. दीपक रोहाल को 627
4. नोटा को 15 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 32 न्यू शिमला में 1461 मतों में से

1. **निशा ठाकुर को 749 विजयी भाजपा**
2. कुसुम लता ठाकुर को 691
3. सत्या भरयाल को 13
4. नोटा को 08 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 33 खलीनी में कुल 2345 मतों में से

1. **चमन प्रकाश को 1158 विजयी कांग्रेस**
2. दलीप सिंह को 10
3. पूर्णमल को 1150
4. नोटा को 27 मत प्राप्त हुए।

वार्ड न. 34 कनलोग में कुल 1874 मतों में से

1. आरती शर्मा को 41
2. **आलोक पठानिया को 1084 विजयी कांग्रेस**
3. अनिल कौंडल को 77
4. बृज सूद को 650
5. नोटा को 22 मत प्राप्त हुए।

पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्रालय से वन मंजूरी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। ऊना में पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के निर्माण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने वन मंजूरी प्रदान कर दी है, जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण की बड़ी बाधा दूर हो गयी है। यह जानकारी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने इस मामले को केंद्र सरकार के साथ मजबूती से उठाया और निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना के निर्माण से ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्वास्थ्य संस्थान का शिलान्यास मार्च, 2018 में किया गया था, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है और केंद्रीय मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद अब शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न महत्वकांक्षी परियोजनाओं की वन मंजूरी के मामले केंद्र सरकार के समक्ष प्राथमिकता के आधार उठा रही है। राज्य सरकार ने एफसीए और एफआरए के मामलों में स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए फारेस्ट क्लीयरेंस कंसल्टेंट आर्गनाइजेशन (एफसीसीओ) के माध्यम से उपयोगकर्ता एजेंसियों को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एफसीए और एफआरए क्लीयरेंस के मुद्दे को प्रभावी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इसकी पूर्व अनुमति की शर्त को हटा दिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को उनके घर-द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें विशेष चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने में किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।

सरकार संचार को बनाए स्कूली पाठ्यक्रमों का हिस्सा:राजीव खन्ना

शिमला/शैल। डिजिटल बाल मेला द्वारा आयोजित और एल. आई. सी. द्वारा प्रायोजित ''बच्चों की सरकार कैसी हो?'' अभियान के तहत आयोजित हुए संवाद सत्र में देशभर में विख्यात पत्रकार और दी सिटीज़नशिप के एसोशिएट एडिटर राजीव खन्ना ने बच्चों से बातचीत की। ''पत्रकारिता और पहाड़ी क्षेत्र की चुनौतियां'' विषय आयोजित इस सत्र में राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय सोलन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बटवार (कांगड़ा), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुर्गापुर (शिमला) सहित देश के कई हिस्सों से विद्यार्थी जुड़े।

सोलन के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिवानी द्वारा पत्रकारिता में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए राजीव खन्ना ने जनसंचार को स्कूली पाठयक्रम में शामिल करने की आवश्यकता बताई और कहा कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहते हैं लेकिन आज भी अभिभावकों का पत्रकारिता में अपने बच्चों के करियर के प्रति रुझान कम है। लिहाजा यह जरुरी है कि पत्रकारिता विषय की जानकारी स्कूल के समय से ही विद्यार्थियों को दी जाये।

इस दौरान हिमाचल प्रदेश के यथार्थ, शिवानी, वर्षा, कुसुम, विजय सिंह चौहान, राजस्थान के पियूष गोयल, परस माली, ललिता बबल, शैताना राम चौधरी, बिहार के सैयद फरहान हैदर, उत्तराखंड के प्रियांशु भट्ट, सहित कई बच्चों ने अपने प्रश्न राजीव खन्ना के समक्ष प्रस्तुत किये, जिनके जवाब देकर खन्ना ने इन बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत किया। सोलन के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की कुसुम ने जब खन्ना से पत्रकारों पर राजनीतिक दबाव पर प्रश्न पूछा तो खन्ना ने कहा '' राजनीतिक दबाव केवल पत्रकारों पर ही नहीं, सब पर होता है'' जरुरत उस दबाव को लिए बिना अपनी जिम्मेदारी पूरा करने की है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्र में पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों से जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को पत्रकारों के प्रति अपना रवैया सुधारने की जरुरत है, हालांकि अभी इतना बुरा नहीं है, लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है।

बच्चों के प्रश्नों के जवाब देते हुए राजीव खन्ना बोले कि आजकल आपकी खबर को कोई दबा नहीं सकता है क्योंकि आज नए मीडिया का दौर है। यहाँ आपकी खबर छिप नहीं सकती है। उन्होंने बताया कि पत्रकारिता जगत में उन लोगों की कमी है जो खबर की पूरी जानकारी देते हों। जो भी पत्रकार यह काम कर लेगा, वह अपनी नयी पहचान बनाएगा। नए मीडिया में ऐसे कई लोग सामने आ रहे हैं और इन्हीं लोगों ने पत्रकारिता की साख को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है।

आपको बता दें कि इस सत्र का संचालन डिजिटल बाल मेला के प्रतीक शर्मा ने किया था। इस सत्र में सोलन के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल आभा चंदेल मौजूद रही। डिजिटल बाल मेला की जान्हवी शर्मा ने बताया कि कल, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंस राज जी बच्चों से मुख़ातिब होंगे। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बच्चों की राजनीतिक समझ बढाने के लिए 12 जून को शिमला में बाल सत्र के आयोजन का अवसर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बच्चों को बढ़ चढ़कर इस अभियान में भाग लेने का सन्देश दिया है। शिक्षा विभाग की सहभागिता से आयोजित होने वाले विधानसभा बाल सत्र में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में ''बच्चों की सरकार कैसी हो?'' अभियान में बच्चे भाग ले रहे हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

उप-मुख्यमंत्री के पदनाम को भी मिली उच्च न्यायालय में चुनौती

- उप-मुख्यमंत्री और मुख्य संसदीय सचिवों को नोटिस जारी
- सभी याचिकाओं पर होगी एक साथ सुनवाई
- उप-मुख्यमंत्री पदनाम को भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने दी चुनौती
- इन्हीं याचिकाओं के दम पर भाजपा नेता कर रहे सरकार गिरने की भविष्यवाणियां

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार के छः मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को असंवैधानिक करार देकर उन्हें हटाये जाने की गुहार लगाते हुये तीन याचिकाएं प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन चल रही हैं। अब इन्हीं के साथ एक और याचिका भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सतपाल सिंह सत्ती की भी उच्च न्यायालय में दायर हुई है। इस याचिका में मुख्य संसदीय सचिवों के साथ उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का मामला भी उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि मुकेश अग्निहोत्री की शपथ एक मंत्री के रूप में हुई है। लेकिन बाद में सरकार ने उन्हें उप-मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जो कि असंवैधानिक है। इस याचिका पर मुकेश अग्निहोत्री और सभी मुख्य संसदीय सचिवों को नोटिस जारी कर दिये गये हैं और मामले की अगली सुनवाई 19 मई को रखी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता सतपाल जैन मामले की पैरवी कर रहे हैं। स्मरणीय है कि स्व. वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में भी एक बार मुख्य संसदीय सचिव और सचिव नियुक्त किये गये थे। तब इन नियुक्तियों को सिटीजन फोरम के देशबंधु सूद ने चुनौती दी थी और उच्च न्यायालय ने इन नियुक्तियों को असंवैधानिक करार देकर इन लोगों को तुरन्त प्रभाव से हटा दिया था। इस हटाये जाने के खिलाफ तब सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गयी थी। उसके बाद राज्य सरकार ने नये सिरे से इस आशय का एक्ट बना लिया था। लेकिन नये एक्ट के बाद ऐसी नियुक्तियां करने से पहले ही एक्ट को भी प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गयी जो अब तक लंबित है। लेकिन इस चुनौती के बाद आने वाली सरकार ने ऐसी नियुक्तियां ही नहीं की। उधर सर्वोच्च न्यायालय में असम में भी ऐसी ही नियुक्तियां होने का मामला आ गया। असम के मामले के साथ ही हिमाचल की एस.एल.पी. भी टैग हो गयी। इस पर जुलाई 2017 में सर्वोच्च न्यायालय में इन नियुक्तियों को असंवैधानिक और गैरकानूनी ठहराते हुये यह कहा है कि राज्य की विधायिका को ऐसा कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। जुलाई 2017 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम पाठकों के सामने पहले ही रख चुके हैं।

जुलाई 2017 के फैसले के बाद दिसम्बर में भाजपा की सरकार बन गयी और जयराम सरकार ने यह नियुक्तियां नहीं की। लेकिन अब सुक्खू सरकार में उप-मुख्यमंत्री भी नियुक्त करना पड़ा। यही नहीं मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले मुख्य संसदीय सचिव बनाने पड़े। मंत्रिमंडल में मंत्रियों के तीन पद खाली चल रहे हैं। विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली चल रहा है। संविधान का ज्ञान रखने वाले जानते हैं कि संविधान में उप-मुख्यमंत्री नाम से कोई पद नही है। भले ही किसी की शपथ उप-मुख्यमंत्री के तौर पर ही क्यों न हुई हो। जब भी ऐसी नियुक्ति को चुनौती दी जायेगी तो वह कानून मानकों पर ठहर नहीं पायेगी। इस समय हिमाचल के उप-मुख्यमंत्री और मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है। कानून के जानकारों के मुताबिक इस पर जब भी उच्च न्यायालय का फैसला आयेगा वह इन नियुक्तियों के पक्ष में नहीं होगा। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह फैसला आ ही जायेगा माना जा रहा है। माना जा रहा है कि यह फैसला आने के बाद प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। भाजपा इस मामले में प्रत्यक्ष रूप से पार्टी बन चुकी है यह स्पष्ट हो चुका है। संभवतः इसी आधार पर भाजपा नेता प्रदेश सरकार के गिराने की भविष्यवाणियां कर रहे हैं।

कौन होगा शिमला का अगला मेयर

- कैग ने शिमला जल प्रबंधन निगम पर उठाये सवाल
- नये सदन के लिये होगा यह बडा मुद्दा

शिमला/शैल। नगर निगम में कांग्रेस को बहुमत मिला है इस नाते महापौर और उपमहापौर दोनों पदों पर कांग्रेस के ही पार्षद चुने जाएंगे यह स्वाभाविक है। कांग्रेस को 24 पार्षदों में से 14 पर महिला पार्षद जीतकर आयी हैं। निगम के कुल 34 वार्डों में से 21 पर महिला पार्षदों की जीत हुई है। इसलिये निगम के सदन में महिलाओं का दबदबा रहेगा यह स्वभाविक है। वरीयता के आधार पर पार्षदों ने अपनी-अपनी दावेदारी भी जताना शुरू कर दी है। कई पार्षद लगातार तीसरी बार चुनकर आये हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके परिवारों का ही अपने-अपने वार्डो पर कब्जा चला आया है। टुटी कण्डी की पार्षद उमा कौशल तो शायद सुखविंदर सुक्खू के साथ भी पार्षद रह चुकी हैं और उस नाते सबसे वरिष्ठ हैं। लेकिन यह चयन केवल वरिष्ठता के आधार पर ही नही होना है। निगम के पिछले सदन में भी महिला महापौर रही है। उनके समय में निगम प्रशासन की क्या स्थिति उसका अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक मामले में एक बार उच्च न्यायालय और दो बार निगम के अतिरिक्त आयुक्त की कोर्ट से फैसले आने के बाद जब उन फैसलों पर अमल करने की गुहार लगाई गयी तो उस पर निगम के पार्षदों की एक कमेटी बनाकर मामले को लटकाने का प्रयास किया गया। जबकि अदालत के फैसले की अपील तो की जा सकती है लेकिन उस पर बदलाव करने के लिये कमेटी नहीं बनाई जा सकती। इस प्रसंग से यह सामने आता है की निगम में पार्षद और फिर महापौर उपमहापौर ऐसे व्यक्ति भी बन जाते हैं जिन्हें नियमों कानूनों की कोई समझ ही नहीं होती और इसकी भरपायी चुनावों में करनी पड़ती है। महापौर- उपमहापौर का फैसला लेते समय कांग्रेस को यह ध्यान रखना होगा कि ऐसे लोगों को यह जिम्मेदारियां दी जाये जो सही में इसके काबिल हों।

इस समय जो 24 पार्षद जीत कर आये हैं उनमें से जिन की शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय स्तर की रही हो और जो कानून की इतनी सी समझ जरूर रखते हो कि अदालत के फैसलों की या तो अपील की जाती है या उस पर अमल किया जाता है। निगम की कमेटी बनाकर फैसले का रिव्यू करना अपने में ही अपराध होता है। ऐसे दर्जनों मामले हैं जहां जानबूझकर लोगों को परेशान किया गया है। इसलिये नये चयन में इसका ध्यान रखना होगा। स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने के संविधान संशोधन में बहुत से कदम सूचीबद्ध हैं। अभी बजट सत्र में स्थानीय निकायों पर आयी कैग रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि सरकार ने इस संबंध में वांछित कदम आज तक नही उठाये हैं।

कैग की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय निकायों में जो वार्ड कमेटियां बनाया जाना अनिवार्य है उनका कई निकायों में गठन तक नही हुआ है। जहां कहां गठन भी हुआ है वहां उनकी बैठकर तक नही हुई है। शिमला निगम में वार्ड कमेटियों की कोई बैठक तक नहीं हुई है। शिमला में पानी की समस्या हल करने के लिये शिमला जल प्रबन्धन निगम का गठन किया गया था। इस पर कैग की टिप्पणी कई सवाल खड़े करती है। इसी से सदन पर भी सवाल उठते हैं जिन पर पार्षदों को जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

यह है कैग की टिप्पणी

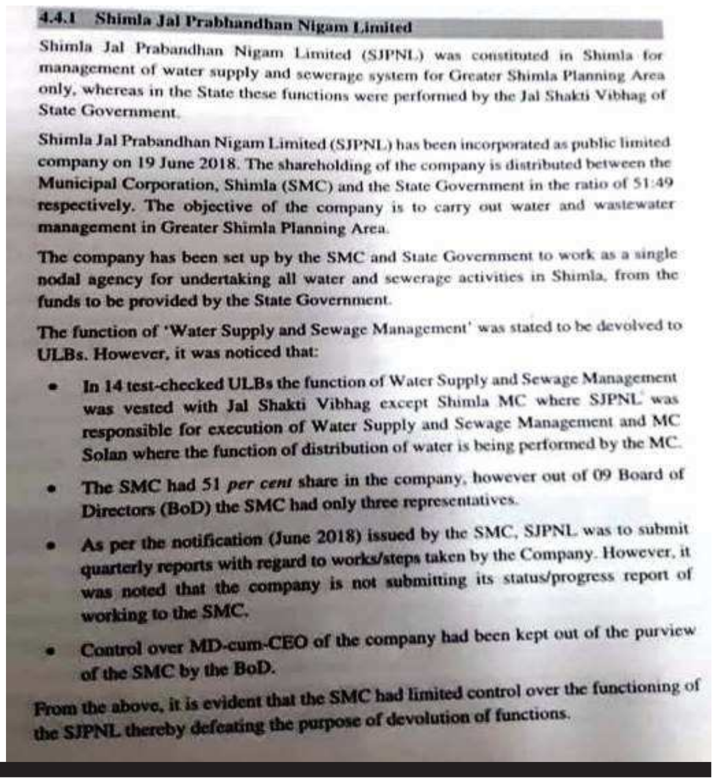

4.4.1 Shimla Jal Prabhandhan Nigam Limited

Shimla Jal Prabandhan Nigam Limited (SJPNL) was constituted in Shimla for management of water supply and sewerage system for Greater Shimla Planning Area only, whereas in the State these functions were performed by the Jal Shakti Vibhag of State Government.

Shimla Jal Prabandhan Nigam Limited (SJPNL) has been incorporated as public limited company on 19 June 2018. The shareholding of the company is distributed between the Municipal Corporation, Shimla (SMC) and the State Government in the ratio of 51:49 respectively. The objective of the company is to carry out water and wastewater management in Greater Shimla Planning Area.

The company has been set up by the SMC and State Government to work as a single nodal agency for undertaking all water and sewerage activities in Shimla, from the funds to be provided by the State Government.

The function of 'Water Supply and Sewage Management' was stated to be devolved to ULBs. However, it was noticed that:

- In 14 test-checked ULBs the function of Water Supply and Sewage Management was vested with Jal Shakti Vibhag except Shimla MC where SJPNL was responsible for execution of Water Supply and Sewage Management and MC Solan where the function of distribution of water is being performed by the MC.
- The SMC had 51 *per cent* share in the company, however out of 09 Board of Directors (BoD) the SMC had only three representatives.
- As per the notification (June 2018) issued by the SMC, SJPNL was to submit quarterly reports with regard to works/steps taken by the Company. However, it was noted that the company is not submitting its status/progress report of working to the SMC.
- Control over MD-cum-CEO of the company had been kept out of the purview of the SMC by the BoD.

From the above, it is evident that the SMC had limited control over the functioning of the SJPNL thereby defeating the purpose of devolution of functions.